बच्चों के मुद्दों पर राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र 2013

पर

बच्चों के साथ संवाद

दिनांक – 20 अक्टूबर 2013

स्थान – पिंक सिटी प्रेस क्लब, नारायण सिंह सर्किल, जयपुर

पहल

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्युमन राइट्स जयपुर
सेव द चिल्ड्रन राजस्थान

बच्चों के मुद्दों पर राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र 2013
पर
बच्चों के साथ संवाद

हर पॉच साल के उपरान्त देश में लोक सभा व राज्यों में विधान सभा के चुनाव होते हैं इन चुनावों के दौरान सभी राजनितिक दल चुनावों में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार कर जनता के सामने आगामी 5 वर्षो के लिए अपनी राज्य की जनता के साथ वादों व कार्यक्रमों के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सामने रखतें है। इन घोषणा पत्र में वह अपने मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़े–बड़े वादे व कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। राजस्थान में भी इस वर्ष 14 वीं विधान सभा के चुनाव एक दिसम्बर 2013 को होने जा रहे है। विगत चुनावों के राजनितिक दलों के घोषणा पत्रों के अध्ययन से निकल कर आया है कि किसी राजनितिक दल के घोषणा पत्र में 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कोई वादे या कार्यक्रम नहीं थे।

राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या 18 साल कम उम्र के बच्चों की है। ये बच्चे मतदाता नहीं है इसलिए वे इन राजनितिक दलों की प्राथमिकता में कभी नही रहे। सभी राजनितिक दल यह मानते है कि बच्चे राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य है परन्तु मतदाता नहीं होने के कारण वे चुनावों में उनकी प्राथमिकता में नहीं रहे।

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स (आर.आइ.एच.आर.) जयपुर व सेव द चिल्ड्रन राजस्थान की पहल पर इस बार होने वाले चुनाव में राजनितिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल करने के लिए एक अभियान की शुरूआत की गई, जिसमें राज्य के सभी राजनितिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल कराने का प्रयास करना सुनिश्चित किया गया इसी को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर 2013 से 10 अक्टूबर 2013 तक राज्य के 14 जिलों में आर. आइ.एच.आर. व सेव द चिल्ड्रन की सहयोगी संस्थाओं के साथ मिल का एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया जिसमें बच्चों के साथ मिल उनके घोषणा पत्र में बच्चों की मागों को शामिल करवाया जा सके। साथ ही राज्य स्तर पर सभी बच्चों के साथ एक दिवसीय संवाद आयोजित किया जाये जिसमें बच्चों के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये जिसमें बच्चे अपनी मागों को राजनीतिक दलों के सामने रखें।

पूर्व में इस राज्य स्तरीय संवाद के आयोजन की तिथि 25 अक्टूबर तय की गई थी परन्तु शिक्षा विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि 23 से 26 अक्टूबर तक बच्चों के अर्द्ध वार्षिक मुल्यांकन तय है अतः इसको परिवर्तीत करके 20 अक्टूबर किया गया।

अभियान का उद्देश्य

- राज्य की सभी राजनीतिक पार्टीयों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल करवाना।
- तथा बच्चों के द्वारा अपनी मागों को राजनीतिक दलों के सामने रखना।

अभियान का क्षेत्र

इस अभियान को राज्य के 14 जिलों की 17 पंचायत समितियों व जिला स्तर पर आयोजित किया गया। ये जिले व पंचायत समितियॉ निम्न प्रकार थी।

क्रम सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति	संस्था जिसने अभियान में हिस्सा लिया
1	अजमेर	किशनगढ़	प्रयत्न संस्था
2	अलवर	तिजारा	एमीड
3	बारा	छिपाबड़ोद	अशोका तकनिकी विकास संस्था
4	बाड़मेर	शिव व चोहटन	नेहरू नवयुवक मण्डल रोहीड़ी, बाडमेर
5	बूदीं	नैनवा	मंजरी संस्था
6	कोटा	कोटा	खिलती कलियॉ
7	पाली	रायपुर	स्थाई विकास सस्थां
8	झालावाड़	झालरापाटन	सामाजिक विकास सस्थां, झालारापाटन
9	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	रणथम्बोर आर्ट एवं वाईल्ड लाइर्फ सोसायटी सवाइमाधोपुर
10	डुंगरपुर	डुंगरपुर, व बिच्छीवाड़ा	पिडो व सेव द चिल्ड्रन
11	भरतपुर	नदबई व कांमा	सार्ड व प्रयत्न संस्था
12	टोंक	टोंक	शिव शिक्षा समिति
13	चितोड़गढ़	चितोड़गढ़	कट्स
14	नागौर	कुचामन सिटी	अलारिप्पु

अभियान की शुरूआत

एक अक्टूबर 2013 को सभी 14 जिलों की 17 पंचायत समिति व जिला स्तर पर संस्थाओं के साथियों ने अपने–अपने कार्यक्षेत्र में विद्यालयों के बच्चों के साथ संवाद करना प्रारम्भ कर दिया था इस दौरान बच्चों व उनके माता–पिता को कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया गया। इसी प्रकार संस्था कार्मिकों को द्वारा सरकारी व निजी विद्यालयों में भी संम्पर्क किया गया तथा वहॉ भी बच्चों के

साथ बच्चों के मुद्दों पर चर्चा की गई। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के मध्य ब्लाकस्तर/जिला स्तर पर बच्चों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जहॉ बच्चो के साथ चर्चा करके बच्चों सम्बन्धित मुद्दों जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व विकास शामिल है, पर चर्चाएं की गई तथा बच्चों के साथ मिल कर उनका मॉग पत्र बनाया गया। कुछ जिलों में इसे अखबार में भी प्रकाशित करवाया गया।

मॉग पत्र की निर्माण कार्यशाला 10 अक्टूबर 2013

ब्लाक व जिला स्तर पर तैयार मॉग पत्रों के साथ दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को राज्य स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर में किया गया जिसमें अभियान से जुड़ी सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में ब्लाक स्तर/जिला स्तर पर बच्चों के द्वारा तैयार किये गये मॉग पत्रों के आधार पर एक समेकित मॉग–पत्र तैयार किया गया।

पूर्व में सभी को राज्य स्तरीय संवाद की तिथि 25 अक्टूबर 2013 घोषित की गई थी। कार्यशाला के दौरान जानकारी में आया व शिक्षा विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि 23 से 26 अक्टूबर तक बच्चों के अर्द्ध वार्षिक मुल्यांकन तय है अतः सबकी सहमति से इसको परिवर्तित करके 20 अक्टूबर किया गया। इसके कारण कई सारी व्यवस्थाएं जो पूर्व में निर्धारित की जा चूकी थी उनको बदलने का निर्णय लेना पड़ा।

कार्यशाला के अन्त में सभी के साथ मिलकर 20 अक्टूबर के राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि सभी संस्थाएं अपने– अपने कार्यक्षेत्र से दो–दो बच्चों (सम्भव हो तो एक बालक व एक बालिका) को तथा उनके अभिभावक भी आना चाहे तो उनके साथ दिनांक 19 अक्टूबर को ही जयपुर आ जायेगें। 19 अक्टूबर को बच्चों के चर्चा करके 20 तारीख की तैयारी की जायेगी। चर्चा के दौरान सेव द चिल्ड्रन की बच्चों की सुरक्षा निति के बारे में बताया गया तथा सभी को इसकी अनिर्वाय रूप से पालना करने के निर्देश दिये।

तैयारी बैठक 19/10/2013

2013 के लिए राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्वों पर को शामिल करने के उद्देश्य 20 अक्टूबर को होन वाली राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम की तैयारी बैठक दिनांक 19/10/2013 को आई.डी.एस. में आयोजित की गई। इस बैठक में घोषणा पत्र से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा की गई। बच्चो के साथ चर्चा करके उनके अलग अलग समूह बनाये गये तथा अलग–अलग मॉगों पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई।

इस मॉग पत्र को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मिड़िया के सामने बच्चें किस प्रकार रखे, इसके लिए बच्चों के ग्रुप तैयार किए, कौनसा ग्रुप किस समस्या पर बात करेगा, मंच संचालन कौन करेगा।

मंच संचालन, स्वागत् एवं धन्यवाद के साथ–साथ अपनी बात को रखने की जिम्मेदारी ली।

बच्चों के मुद्वो पर एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम

राजस्थान विधान सभा चुनाव 2013 में राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्वों को शामिल करवाने के संदर्भ में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 को पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया।

संवाद कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री विनोद यादव, नेशनल पीपुल्स पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष सुश्री चारु गुप्ता, कम्युनिष्ठ पार्टी की सुश्री राजकुमारी डोगरा, निर्दलीय पार्टी के विजय पाल जी, विभिन्न समाचार पत्रों व इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर्मियों सहीत राजस्थान के 18 जिलों से लगभग 250 संम्भागी जिनमें 135 से अधिक बच्चे उपस्थित थे।

संवाद कार्यक्रम के मंच संचालन का संचालन बालिका तसलीम व धर्मराज द्वारा किया गया। संवाद कार्यक्रम का शुभारम्भ बालिका कृतिका एवं मौसम द्वारा स्वागत् गीत से किया गया।

संवाद कार्यक्रम का उद्वेश्य बताते हुए आर.आइ.एच. आर. के महासचिव विजय गोयल ने कहा कि राजनितिक दल चुनावों में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार कर जनता के सामने आगामी 5 वर्षो के लिए अपनी राज्य की जनता के साथ वादों व कार्यक्रमों के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सामने रखेगें। इस घोषणा पत्र में वह अपने मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़े–बड़े वादे व कार्यक्रमों की घोषणा करेगें। विगत चुनावों के राजनितिक दलों के घोषणा पत्रों के अध्ययन से निकल कर आया है कि किसी राजनितिक दल के घोषणा पत्र में 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कोई वादे या कार्यक्रम नहीं थे। उन्होने कहा कि राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या 18 साल कम उम्र के बच्चों की है। ये बच्चे मतदाता नहीं है इसलिए वे इन राजनितिक दलों की प्राथमिकता में कभी नही रहे। सभी राजनितिक दल यह मानते है कि बच्चे राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य है परन्तु मतदाता नहीं होने के कारण वे चुनावों में उनकी प्राथमिकता में नहीं रहे। इस संवाद कार्यक्रम में बच्चों के मुद्वों को समेकित कर जो मॉग पत्र तैयार किया गया। उस मॉग पत्र को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात को रख सके।

तसलीम ने कहा कि ''राज्य कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। हम बच्चें हमारे देश का भविष्य है, परन्तु राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में हम बच्चों की समस्याओं को प्राथमिकता नही मिलती है क्योंकि हम किसी भी पार्टी के मतदाता नहीं है। बच्चों ने अपनी मॉगों को रखते हुए सबसे पहले भानूप्रताप, संजय जाट, प्रकाश, परमेश्वरी आदि बच्चों ने सुरक्षा को लेकर आने वाली समस्याऍ के बारे में कहा है कि राज्य में 12 लाख बच्चें बाल श्रम में लगे हुए है। बाल श्रम में राज्य तीसरे

स्थान पर है। जिला स्तर स्वास्थ्य सर्वे 2007–08 के अनुसार हर पॉच में से दो बालिकाओं का बाल विवाह हो जाता है। 2007 के अनुसार राज्य में बाल शोषण 50 प्रतिशत तक है। परमेश्वरी का कहना था कि जब बच्चे बाल श्रम में लगते है तो उनके साथ कई प्रकार से शोषण होता है, वहॉ बच्चे नशे की प्रवृति में घूस जाते है उनके साथ काम की जगह पर मार–पीट होती है खाने को भर पेट नहीं मिलता है। जिला स्तर स्वास्थ्य सर्वे 2007–08 के अनुसार हर पॉच में से दो बालिकाओं का बाल विवाह हो जाता है। 2007 के अनुसार राज्य में बाल शोषण 50 प्रतिशत तक है। इन समस्याओं के लिए अपनी मॉगों को रखते हुए कहा कि

- जिला स्तर पर एक स्वतत्रं बाल न्यायालय हो।
- मानव तस्करी विरोधी इकाई का प्रत्येक जिले में गठन एवे सक्रियता सुनिश्चित हो।
- बच्चों की नशा प्रवृति को रोकने के लिए नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना हो।
- बाल श्रम को संज्ञेय मानते हुए बाल श्रम करवाने वालो के खिलाफ कानून सख्ती से लागू किया जाए।
- मानसिक व विमंदित बच्चों के लिए संचालित गृहों में प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति की जाए।
- बाल विवाह को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर सरपंच या सचिव की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

सतीष, राहुल, नैनसी, परमेश्वरी एवं अन्य बच्चों ने शिक्षा को लेकर जो समस्याए सामने आ रही है उनके बारे में बताया कि हर पॉच में से एक बच्चा शिक्षा से वंचित है। कई विद्यालयों में छात्रों के अनुसार अध्यापक नही है। विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा नही है। पुस्तकालय नही है। 2010 के चाइल्ड टैकिगं सर्वे के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 12.2 लाख बच्चें शिक्षा से वंचित है। ऐसी ही बहुत सी समस्याओं को लेकर हम बच्चों की मॉग है कि

- प्रत्येक विद्यालयों में एक पद चपरासी का हो जो विद्यालय के अन्य कार्य कर सके जिससे बच्चों को विद्यालय में काम नही करना पडे।
- प्रत्येक गांव में मौसम अनुकूल विद्यालय भवन हो।
- विद्यालयों की चार दीवारी हो।
- विद्यालयों में खेल का मैदान हो।
- विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए अलग से शौचालए की व्यवस्था हो।

- विद्यालयों में महिला अध्यापिका की अनिवार्यता सुनिस्चित हो।
- गांव में आंगनबाडी केन्द्र हो जिससे शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को मिल सके।
- मानसिक व विमंदित बच्चों के लिए प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करे।
- विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो और बच्चों से विद्यालयों में सफाई का काम करवाना पूर्ण रूप से बंद हो।
- विद्यालयों में मिलने वाला मिड डे मील गुणवत्ता पूर्ण हो।

शैलेन्द्र, शारूख, कल्याण सिंह,राधा, दिव्या एवं अन्य बच्चों ने स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्या को सबके सामने रखा। उन्होने बताया कि ''हमारे राज्य में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पर 57 है।जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 38 बच्चें अपने जन्म के पहले महिने में ही जीवन त्याग देते है। कई बच्चें कुपोषण का शिकार हो रहे है। इन सभी समस्याओं को लेकर मागॅ करते है कि–

- प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ हो।
- ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जॉच हो।
- सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से टीकाकरण हो। स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धरित सभी टीके निशुल्क उपलब्द हो।
- पोषण युक्त सामग्री की व्यवस्था हो।
- विद्यालय में होने वाली जॉच को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- कुपोषण से पीडित बच्चों को राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनाया जाए।

मौसम, लीलावती, विनय, कृतिका, राहुल, सौरभ, पुष्कर एवं अन्य बच्चों ने विकास से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सर्वे 3 के अनुसार 44 प्रतिशत बच्चें कुपोषण का शिकार है। आदिवासी क्षेत्रो में 90 प्रतिशत तक बच्चें कुपोषित है। राज्य में बच्चों के विकास पर कुल बजट का 1.58 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है। अतः हमारी मॉग है कि

- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा की व्यवस्था हो।
- प्रत्येक गांव में बच्चों की पहुॅच में सभी सुविधा युक्त आंगनबाड़ी केन्द्र हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर दिया जाने वाला पोषाहार गुणवत्ता पूर्ण हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए।

- स्कूल स्तर पर ऐसा केन्द्र खोला जाए जहॉ पर बच्चों से सम्बन्धित कानून की जानकारी मिल सके।
- बच्चों को सुन जाने हेतु पंचायत स्तर पर एक हेल्प डेस्क व सुझााव बॉक्स हो।

रामबाई, नीबू, मॉगीबाई, दीपक एवं अन्य बच्चों का कहना है कि

- बच्चों के विद्याालय आने–जाने के लिए सरकारी व निजि बसों में फ्री पास की सुविधा होनी चाहिए।
- जो घर से बच्चें भागते है उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।
- विद्याालय में ऐसे अध्यापक हो जो बच्चों को मारे नही।
- साईकिल सभी बच्चों को मिलनी चाहिए चाहे वह दूर का हो या पास का।
- बच्चों का कहना है कि चुनावों से पहले तो विधायक घोषणा कर देते है लेकिन बाद में कुछ नही करते।

राजनीतिक दलों की ओर बच्चों कि मागों पर अपना पक्ष रखते हुए राष्ट्रीय जन पार्ट्री की महिला मोर्चा अध्यक्ष सुश्री चारू गुप्ता ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में बच्चें की मॉगों को रखने का आश्वासन दिया और कहा कि इनकी जो भी मॉग है वह जायज है कोई बहुत बडी नही है। इनमें किसी प्रकार की कटोती नही होनी चाहिए। यह बच्चे हमारी भावी पीढी है, हमारे देश का भविष्य है। यह बच्चे अभी से सक्रिय हो गये है तथा अपनी मॉगों व अपनी बात को कहना सीख रहे है।

कम्युनिष्ट पार्टी से सुश्री राजकुमारी डोगरा का कहना था कि शिक्षा को लेकर जो कानून बना था एसमें 25 प्रतिशत वाले बच्चों को किसी न किसी तरह से टाला जाता है। उन्होने बच्चों की मॉग को पार्टी के घोषणा पत्र में रखने का आश्वासन दिया।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री विनोद कुमार यादव ने बच्चों की मॉग को पार्टी के घोषणा पत्र में रखने का आश्वासन देते हुए कहा कि आज इन बच्चों की बात को सुन कर हमारा भी बचपन याद आ गया, पहले बच्चे अध्यापक का सम्मान करते थे और आज अगर बच्चे को जरा सा मार दो तो विद्यालय से भाग जाता है। पहले ऐसा नही होता था। इनका कहना था कि अगर अध्यापक डाटता है तो अपने ही भविष्य को बनाने के लिए वह ऐसा करता है इस लिए उनकी मार का बुरा नही मानना चाहिए। आज शिक्षा में जो भी बदलाव आ रहा है वह बच्चो के बदलते व्यवहार से है। बच्चों को कभ्सी कमजोर नही समझना चाहिए। साथ ही कहा कि बच्चों के लिए स्वतत्रं बाल न्यायालय होना चाहिए।

निर्दलीय श्री विजय पाल ने कहा कि ''जनता किसी पार्टी की गुलाम नही है। इन नेताओं को भी पार्टी वाद ने अन्धा कर दिया है। कुछ बडी पार्टीया छोटी पार्टीयों को शामिल कर लेती है। उन्होंने कि आज इन बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के सदस्य उपस्थित नही हुए इससे साफ जाहिर हो रहा है की उन्हे इन बच्चों की कितनी चिन्ता है यह कहते हुए चाचा नेहरु याद आ गये। उनका कहना था कि जिन्हे हम भविष्य निर्माता कहते है वह अध्यापक तो खुद भ्रष्ट है साथ ही बी. एड. कॉलेजो की स्थिति से अवगत करवाया। जो अध्यापक फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे है वह कहॉ से गुणवत्ता वाले होगें।

मंच पर राजनितिक दलों के प्रतिनिधि

कार्यक्रम के अन्त में सेव द चिल्ड्रन के राज्य प्रबन्धक श्री प्रभात कुमार ने सबका धन्यवाद देते हुए कहा कि *''जितने अच्छी तरह से बच्चों ने अपने मुद्दों को जितनी अच्छी तरह से रखा, इतनी अच्छी डिबेट आज जिस तरह से बच्चों ने किया वो राजनीतिक दलों के लोग भी नहीं कर सकते है इसके लिए सभी बच्चों को बहुत–बहुत धन्यवाद।''* श्री प्रभात ने सभी बच्चों से आवहान किया कि जब एक दिसम्बर 2013 को आपके परिवार के माता–पिता, रिश्तेदार दादा–दादी नाना–नानी जो भी हो वो वोट देने जाये तथा सही व्यक्ति को वोट दे ताकि विधान सभा में आपकी बातों को ढ़ग से रख सके।

बच्चों के साथ ब्लाक स्तर/जिला स्तर पर कार्यशालाएं

डुंगरपुर में बच्चों के साथ कार्यशाला के उपरान्त अपना मॉग पत्र दिखाते हुए।

बिच्छीवाड़ा में बच्चे मॉगों पर चर्चा करते हुए

पाली जिले के रायपुर ब्लाक में विद्यालयों बच्चे मॉगों पर चर्चा करते हुए।

सवाईमाधेपुर में विद्यालयों बच्चों के साथ चर्चा करते हुए।

चित्तोड़गढ में बाल मंच के बच्चों के साथ बच्चों के मॉग पत्र पर चर्चा करते हुए।

बॉरा जिले के छिपाबडोद कस्बे में विद्यालय में बच्चों के साथ बच्चों के मॉग पत्र पर चर्चा करते हुए

कोटा शहर में नीजि विद्यालय में बच्चे मॉग पत्र पर चर्चा करते हुए

अलवर जिले के तिजारा ब्लाक में बाल मंच के बच्चों के साथ मॉग पत्र पर चर्चा करते हुए।

झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में सरकारी विद्यालय में बच्चों के साथ मॉग पत्र पर चर्चा करते हुए।

भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में बाल मंच व विद्यालय के बच्चे मिलकर मॉग पत्र पर चर्चा करते हुए।

बाडमेर शहर में सरकारी विद्यालय के बच्चों के साथ मॉग पत्र पर चर्चा करते हुए।

बच्चों के साथ हुई कार्यशालाओं पर अखबारों की नजर

अलवर केसरी
पंजाब केसरी

बाल मंच के सरपंचों की कार्यशाला

राजस्थान पत्रिका भरतपुर, बुधवार 09.10.2013 **भरतपुर**

सेव द चिल्ड्रन पर कार्यशाला

नदबई. यहां कुम्हेर रोड स्थित कार्यालय पर मंगलवार को सेव द चिल्ड्रन के तहत कार्यशाला हुई। इसमें विद्यार्थियों ने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं शीर्षक पर विचार व्यक्त कर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की

विभिन्न समस्याओं को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की। इस दौरान संस्था परियोजना

अधिकारी मानवेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुन्दर सिंह, मुकुल कटारा, राजवीर सिंह शामिल थे।

बच्चों ने तैयार किया चुनावी मांग पत्र

न्यूज सर्विस

चित्तौड़गढ़, 6 अक्टूबर। स्वयंसेवी संगठन 'कट्स' मानव विकास केन्द्र पर सेव द चिल्ड्रन द्वारा आयोजित 'सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में उपेक्षित बच्चों की भागीदारी परियोजना' के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों ने आने वाले चुनावों के लिए अपने अधिकारों के लिये मांग पत्र तैयार किया। कट्स के केन्द्र समन्वयक धर्मवीर यादव ने बताया कि सभी राजनीतिक दल चुनावों में पार्टी का घोषणा पत्र तैयार कर जनता के सामने आगामी 5 वर्षों के लिए वादों व कार्यक्रमों के लिए घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगें। यादव ने बताया कि विगत चुनावों के राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के अध्ययन से निकल कर आया है कि किसी राजनितिक दल के घोषणा पत्र में 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कोई वादे या कार्यक्रम नहीं हैं।

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर व सेव द चिल्ड्रन राजस्थान की पहल पर इस बार होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें राज्य के सभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल कराने का प्रयास करने हेतु ब्लॉक स्तरीय बाल पंचायत के बच्चों द्वारा मांग पत्र तैयार किया गया। यह मांग पत्र 25 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यशाला में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यशाला में बच्चों के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, बच्चे अपनी मांगें प्रतिनिधियों के सामने रखेंगे। कार्यशाला में चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की सावा, सामरी, शंभुपुरा, घटियावली, ऐराल एवं नेतावल गढ़ पाछली ग्राम पंचायतों के 28 गांवों के ब्लॉक स्तरीय बाल पंचायत के 13 बच्चों ने भाग लेकर यह मांग पत्र तैयार किया।

चित्तौड़गढ़। कार्यशाला में मांग पत्र तैयार करते बच्चे। फोटो : नवज्योति

Navjyoti Pg:8 Date 8/10/2013

घोषणा पत्र में बच्चों की मांगों को शामिल करें राजनैतिक दल

बच्चों ने राजनेताओं के समक्ष रखी अपनी मांगें.

डूंगरपुर, 8 अक्टूबर। आगामी दिसम्बर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगले 5 वर्षों के लिए सभी राजनितिक दल चुनावों में अपनी पार्टी का मतदाता को आकर्षित करने के लिए बड़े-बड़े वादों व कार्यक्रमों वाला घोषणा पत्र तैयार कर जनता के सामने रखेंगें। लेकिन इस बार छोटे बच्चों ने भी राजनेताओं के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं जिन्हें जनप्रतिनिधियों को संजीदगी से सोचना होगा।

सेव द चिल्ड्रन के परियोजना अधिकारी हरिश चंदेरिया ने बताया कि विगत चुनावों के राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों के अध्ययन से निकल कर आया कि किसी भी राजनैतिक पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोई वादे या कार्यक्रम नहीं थे। रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट जयपुर व सेव द चिल्ड्रन राजस्थान की पहल पर इस बार होने वाले चुनाव में राजनैतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दो को शामिल करवाने के लिए एक अभियान की शुरूआत की गई जिसके मंगलवार को बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा परियोजना क्षेत्र के डूंगरपुर व बिछिवाड़ा पंचायत समिति के बच्चों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चयनित 20 पंचायतो के 17 बालक व 23 बालिकाओं ने भाग लिया।

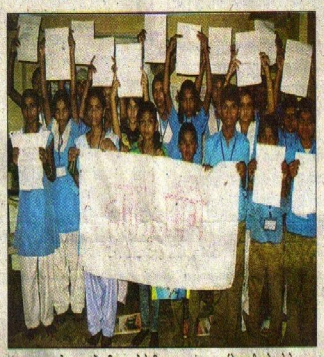

संस्था के क्षेत्र अधिकारी संजय मौड़ ने बताया कि कार्यशाला में भाग लेने वाले बच्चे पंचायत स्तर पर नवगठित 'पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति' के सदस्य है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के मुद्दों को राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में लाने के लिए बच्चों के साथ चर्चा कर मांग पत्र तैयार करवाना है। कार्यशाला में संस्था कार्यकर्ता गजेन्द्र गोहिल व पीड़ो संस्था से नवीन रावल आदि मौजूद थे।

बच्चों के द्वारा बनाये गये इस मांग पत्र को आगामी 25 अक्टूबर को जयपुर में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय कार्यशाला में बच्चों के द्वारा उनके समक्ष रखा जायेगा।

डूंगरपुर। चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए अपना मांग पत्र दर्शाते स्कूली बच्चे। फोटो-आयुष

20 अक्टूबर 2013 को संवाद के पल

PINK CITY PRESS CLUB
बच्चों के साथ संवाद

बच्चों के साथ संवाद
दिनांक – 20 अक्टूबर 2013

20 अक्टूबर संवाद अखबारों की नजर में

मॉर्निंग न्यूज

जयपुर, शनिवार 19 अक्टूबर, 2013

बच्चों ने तैयार किया मांगपत्र

जयपुर, 18 अक्टूबर (मोन्यू)। सरकारी स्कूलों में बच्चों को कक्षा कक्ष, अध्यापक खेल का मैदान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अस्पतालों में इलाज मिले, साथ ही बच्चों की सुरक्षा, विकास आदि मांगों के लेकर बच्चों ने अपना मांग पत्र तैयार किया है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए बनाया गया यह मांगपत्र 20 अक्टूबर को पिंक सिटी प्रेस क्लब में राज्य के विभिन्न जिलों के 50 से अधिक बच्चे राजनीतिक दलों व मीडिया के सामने रखेंगे।

सभी दल चुनावों में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करते हैं लेकिन राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या 18 साल कम उम्र के बच्चों की होने के बावजूद राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में उनकी समस्याओं को प्राथमिकता नहीं मिलती है। रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर व सेव द चिल्ड्रन बाल रक्षा भारत की पहल पर इस बार होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल करने के लिए एक अभियान की शुरूआत की है।

डेली न्यूज़ 8

जयपुर, सोमवार
21 अक्टूबर 2013

पार्टियों के सामने बच्चों ने रखी मांगें

जयपुर। रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर व सेव द चिल्ड्रन बाल रक्षा की ओर से रविवार को आयोजित कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए 150 बच्चों ने राजनीतिक दलों के सामने मांगें रखीं। उन्होंने बाल विवाह रोकने, नशा मुक्ति केंद्र खोलने, हर सरकारी स्कूल में कक्ष और खेल का मैदान बनवाने जैसे मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही। इस मौके पर सपा के प्रदेश महासचिव विनोद यादव, नेशनल पीपुल्स पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चारू गुप्ता, कम्युनिस्ट पार्टी से राजकुमारी डोगरा ने बच्चों की मांगों का समर्थन किया।

दैनिक नवज्योति

जयपुर, सोमवार, 21 अक्टूबर 2013

बच्चों ने स्वतंत्र न्यायालय के गठन की मांग की

नवज्योति ब्यूरो/जयपुर

राजस्थान में करीब 47 प्रतिशत आबादी बच्चों की है और वे चाहते हैं कि प्रदेश में स्वतन्त्र बाल न्यायालय का गठन किया जाए तथा बाल विवाह को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

आगामी एक दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से रविवार को आयोजित संवाद में प्रदेश के 18 जिलों से शरीक हुए 150 से अधिक बच्चों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए। बच्चों का कहना था कि राजनीतिक दलों के नेता भाषणों में तो यह मानते हैं कि बच्चे राष्ट्र का वर्तमान एवं भविष्य है लेकिन अपने घोषणा पत्र में बच्चों की अहम समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। संवाद में आए बच्चों को उम्मीद थी कि दूर दराज से आए बच्चों की भावनाओं को सुनने के लिए प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे लेकिन आयोजकों के बुलावे के बावजूद वे नहीं आए। संवाद में शरीक हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव विनोद यादव, नेशनल पीपुल्स पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चारु गुप्ता तथा कम्युनिस्ट पार्टी की राजकुमारी डोगरा ने बच्चों को आश्वस्त किया कि वे अपनी अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल कराएंगे।

राजस्थान पत्रिका

जयपुर . सोमवार
21.10.2013

घोषणा पत्र के लिए बच्चों ने सौंपे मांग पत्र

■ 18 जिलों के 100 बच्चों ने रखी अपनी मांगें

जयपुर

jaipur@patrika.com

'भले ही हमारा वोट नहीं है, लेकिन आखिर हमारे मुद्दे, हमारी समस्याएं और हमारे सपने भी तो पूरे होने हैं।' 18 जिलों से आए बच्चों ने रविवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मांग पत्र पेश किया।

आरआईएचआर और सेव द चिल्ड्रन की ओर से प्रेस क्लब सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों ने उनसे जुड़े मुद्दे सामने रखे। कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन सपा, राजपा और सीपीएम के प्रतिनिधि ही पहुंचे। संवाद कार्यक्रम में बच्चों ने कहा कि वे प्रदेश की आबादी के 47 प्रतिशत है। सभी राजनीतिक दल उनके मांगपत्र को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाएं।

कार्यक्रम संयोजक विजय गोयल ने बताया कि ये मांग पत्र सभी राजनीतिक दलों को बच्चों ने खुद जाकर सौंपे।

यह चाहते हैं बच्चे

- हर स्वास्थ्य केंद्र पर शिशु रोग विशेषज्ञ मौजूद हों, हर अस्पताल में टीकाकरण की व्यवस्था हो, बच्चों का देखभाल कक्ष हो।
- सभी स्कूलों में पर्याप्त भवन, कक्षा कक्ष, शिक्षक हों।
- खेलकूद के लिए व्यवस्थाएं हों।
- जिला स्तर पर बाल अदालत गठित हो।
- बच्चों के लिए विशेष पुलिस थाना।
- बाल श्रम पर रोक के लिए कड़ी व्यवस्था हो।
- आंगनबाड़ी में प्री-स्कूल शिक्षण हो।
- बाल विवाह को रोकने के प्रयास हों, कार्रवाई के लिए विशेष प्रकोष्ठ हो।

पंजाब केसरी **राजस्थान** 21 अक्तूबर, 2013 सोमवार

स्वतंत्र बाल न्यायालय बने

बच्चों ने की आगामी सरकार से मांग

प्रदेश में नशा मुक्ति केन्द्र व मौसम अनुरूप हो विद्यालय भवन

पिंकसिटी प्रेस क्लब में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद करते बच्चे।

जयपुर,(कासं): प्रदेश में कुल आबादी का करीब 47 फीसदी आबादी प्रतिशत हम बच्चों का है, तो फिर बच्चों की मांगों को क्यों अनुत्तरित किया जाता रहा है! आज हम आगामी विधानसभा चुनाव होने पर अनने वाली सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश में स्वतंत्र बाल न्यायालय स्थापित हो।

बाल विवाह रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर सरपंच व सचिव की जवाबदेही हो, बच्चों में नशा रोकने के लिए नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना हो, प्रत्योक ग्राम में मौसम के अनुकूल विद्यालय भवन बना हो, तथा प्रत्येक विद्यालय में शौचालय, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, स्कूल की चार दीवारी एवं खेलकूद का मैदान बना हो। ऐसी ही कुछ मांग रविवार को राज्यभर से आए बच्चों ने पिंकसिटी प्रेस क्लब सभागार में मीडिया के सामने रखी।

मौका था आरआईएचआर एवं सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से आयोजित दिसम्बर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों चुनाव घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को शामिल करवाने के कार्यक्रम का। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 18 जिलों के 150 बच्चों ने शिरकत की। कार्यक्रम में राजनैतिक दलों की ओर से समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश महासचिव विनोद कुमार, नेशनल पीपुल्स पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चारु गुप्ता, कम्युनिस्ट पार्टी की राजकुमारी डोगरा ने बच्चों की इन मांगों का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि यदि पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो वे इन मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

नहीं आए भाजपा व कांग्रेस के प्रतिनिधि

संवाद में भाजपा व कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस की सत्तारुढ़ सरकार के प्रतिनिधि के नहीं आने पर एक वक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि चाचा नेहरु की पार्टी के लोग ही बच्चों को भूल गए हैं, तभी ये नहीं आए। इसके बाद स्वयं बच्चों के दो दलों ने ही इन पार्टी के कार्यालयों में जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

घोषणा पत्र में शामिल हों हमारे मुद्दे

नेशनल दुनिया

जयपुर। जब राज्य की 47 प्रतिशत आबादी बच्चों की है तो राजनीतिक दल बच्चों की मांगों पर ध्यान क्यों नहीं देते। कुछ यही कहना था रविवार को प्रेस क्लब में आरआइएचआर जयपुर व सेव द चिल्ड्रन की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में। कार्यक्रम में बच्चों ने आगामी विधानसभा चुनावों में विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्रों में बच्चों के मुद्दों को भी शामिल करने की पुरजोर मांग की है। कार्यक्रम में राज्य के 18 जिलों से आए 150 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। बच्चों का कहना था कि राजनीतिक दल बच्चों के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते, जबकि बच्चे ही कल का भविष्य होते हैं।

बच्चों ने रखी ये मांगें

बच्चों ने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावों में हमारे मुद्दे शामिल करने होंगे। बच्चों ने स्वतंत्र बाल न्यायालय का गठन करने, बाल विवाह रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर सरपंच या सचिव की जवाबदेही सुनिश्चित करने, बच्चों में नशा प्रवृति रोकने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करने, गावों में मौसम अनुकूल विद्यालय भवन बनाने, स्कूलों में खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, रसोई, शौचालय और चारदीवारी की मांग की। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग व महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की मांग की। ये सभी मांगें विभिन्न राजनीतिक दलों के समक्ष रखी गईं

संवाद कार्यक्रम

- 18 जिलों से आए 150 से अधिक बच्चे
- जब आबादी 47 फीसदी तो फिर अनदेखी क्यों?

राजनीतिक दल थे मौजूद

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव विनोद यादव, नेशनल पीपुल्स पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चारू गुप्ता, कम्युनिस्ट पार्टी से राजकुमारी डोगरा समेत अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। उधर, राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि न होने के चलते बच्चों ने अपनी नाराजगी भी दर्ज करवाई।

सौंपा मांग पत्र

कार्यक्रम में मौजूद राजनीतिक दलों व अन्य दलों के कार्यालयों में जाकर बच्चों के समूहों ने अपना मांग पत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपा और अपनी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने की अपील की।

मॉर्निंग न्यूज

जयपुर, सोमवार 21 अक्टूबर, 2013

बच्चों ने स्वतंत्र बाल न्यायालय मांगा

कांग्रेस भाजपा के नेता नहीं आए, बच्चों को याद आए चाचा नेहरु

जयपुर, 20 अक्टूबर (मोन्यू)

राजस्थान में करीब 47 प्रतिशत आबादी बच्चों की है और वे चाहते हैं कि प्रदेश में स्वतन्त्र बाल न्यायालय का गठन किया जाए तथा बाल विवाह को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की जवाबदेही तय की जाए।

आगामी एक दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सेव द चिल्ड्रन संस्था द्वारा रविवार को यहां आयोजित संवाद में प्रदेश के 18 जिलों से शरीक हुए 150 से अधिक बच्चों ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए। बच्चों का कहना था कि राजनीतिक दलों के नेता भाषणों में तो यह मानते हैं कि बच्चे राष्ट्र का वर्तमान एवं भविष्य हैं लेकिन अपने घोषणा पत्र में बच्चों की अहम समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता नहीं देते।

संवाद में आए बच्चों को उम्मीद थी कि दूर दराज से आए बच्चों की भावनाओं को सुनने के लिए प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे लेकिन आयोजकों के बुलावे के बावजूद वे नहीं आए। कुछ बच्चों ने तो यहां तक कहा कि चाचा नेहरु की पार्टी के नेता भी बच्चों को भूल गए, इसीलिए वे आज हमारी पीडा सुनने नहीं आए।

संवाद में शरीक हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव विनोद यादव, नेशनल पीपुल्स पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चारु गुप्ता तथा कम्युनिस्ट पार्टी की राजकुमारी डोगरा ने बच्चों को आश्वस्त किया कि वे अपनी अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल कराएंगे।